दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शनिवार 18 दिसंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 81

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के तीन साल पूरे

» विभिन्न योजनाओं से राज्य के लोगों के जीवन में आया बदलाव

नई दिल्ली (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुक्रवार को अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं। इन तीन सालों में प्रदेश में 'भूपेश है तो भरोसा है' के नारों के साथ जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। नवीन सरकार के गठन के साथ ही अपने प्राथमिकता में आदिवासियों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों को रख कर योजनाओं का निर्माण किया। इस दौरान कई क्रांतिकारी फैसले लिए, जिसमें 11 लाख किसानों का 9 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ करना और किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी और बिजली बिल हाफ करने का निर्णय भी शामिल है।

प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को अपनी वास्तविक छत्तीसगढ़िया पहचान दिलाते हुए, विकास और न्याय के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ी अस्मिता और स्वाभिमान लौटाने के कदम उठाए। हर वर्ग को अपने प्रदेश की भावना से और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की पहल की। वहीं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। प्रदेश सरकार ने 'छत्तीसगढ़ मॉडल' स्थापित कर जनसशक्तिकरण से आर्थिक विकास की इबारत लिखी है। ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के लिए नई दिशा में कामकाज किया। स्वरोजगार और आजीविका संबंधी गतिविधियों पर फोकस किया। यही कारण है कि मंदी के दौर में भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था टिकी रही। वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिये हितग्राहियों के खाते में नगद हस्तांतरण से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। ग्रामीणों के जीवन में अब बदलाव आने लगा है। किसान जैविक खेती की ओर लौटने लगे हैं। जैविक खेती से लागत हुई आधी, उत्पादन भी दो से तीन गुना तक बढ़ने लगा है।

साल 2020-21 में राज्य गठन के बाद सर्वाधिक 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी का कीर्तिमान बना है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। वनोपजों के समर्थन मूल्य में वृद्धि का फैसला भी आदिवासियों के हित में हितकारी रहा है। वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ पिछले तीन वर्षों में लगातार पूरे देश में अव्वल है। वनोपज से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। वहीं, राज्य को वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण में 11 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति से राज्य में नया औद्योगिक और आर्थिक वातावरण बना है। तीन सालों में राज्य में 1564 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 18 हजार 882 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश से राज्य की तस्वीर बदली है।

राज्य में आम लोगों को लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में सस्ती दवाओं के माध्यम से राहत देने की योजना राज्य सरकार ने लागू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगी ब्रांडेड दवाओं की जगह सस्ती जेनेरिक दवाओं के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की। इस मेडिकल स्टोर में जेनेरिक दवाएं 50 से 70 फीसदी सस्ते दामों पर मिल रही हैं। बिजली बिल में रियायत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गयी हाफ बिजली बिल योजना से निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ 40 लाख उपभोक्ताओं को पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में बदलाव के बयार से समझ आता है कि इन योजनाओं के जरिये भूपेश सरकार निश्चित तौर पर जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रही है।

सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच अगले 2 हफ्ते में हो सकती है पूरी, 14 लोगों की गई थी जान

नई दिल्ली (आरएनएस)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए 14 लोगों की मौत के कारणों की जांच के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से गठित त्रिकोणीय सेवाओं की जांच अगले दो सप्ताह के भीतर पूरी हो सकती है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। जांच का नेतृत्व भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी, देश के सर्वश्रेष्ठ हेलिकॉप्टर पायलट एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह और भारतीय सेना-नौसेना के एक-एक ब्रिगेडियर-रैंक के अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि जांच दल गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है, जिसमें तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में दुर्घटनास्थल के पास घटनास्थल पर मौजूद लोग शामिल हैं। टीम के अगले दो सप्ताह में अपनी कार्यवाही पूरी करने की उम्मीद है। घटना के अगले ही दिन जांच टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एक या दो मामलों में कुछ लोगों ने घटनाओं का लेखा-जोखा बदल दिया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व्यक्तिगत रूप से इस जांच प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी कार्यवाही की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द नाम की घोषणा की जाएगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

तीसरे दर्जे का वकील कहने पर पत्रकार को एक महीने की हुई जेल

नई दिल्ली (आरएनएस)। एक वकील को तीसरे दर्जे का बताना एक पत्रकार को भारी पड़ गया है और इस गलती के लिए उसे एक महीने जेल की सजा भुगतनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि का दोषी पाए गए पत्रकार की याचिका को खारिज कर दिया है। उसे एक महीने की कैद की सजा सुनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा कि आपने किसी को तीसरे दर्जे का वकील कहा। आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो और दावा करते हो कि तुम पत्रकार हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अगुआई वाली बेंच में शामिल जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि अपने लेख की भाषा देखो। सजा को उदार बताते हुए सीजेआई ने कहा कि यह पीत पत्रकारिता है। यह उदारता है कि केवल एक महीने की कैद दी गई है।

एक हजार महिलाओं ने पास की एनडीए की परीक्षा

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के दरवाजे महिलाओं के लिए खोले जाने के बाद हुई पहली परीक्षा में 1002 महिला उम्मीदवारों ने इसे सफलतापूर्वक पास किया है। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, एनडीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 8000 उम्मीदवारों में पहली बार परीक्षा में बैठी 1002 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने एनडीए के दरवाजे महिला उम्मीदवारों के लिए खोल दिए थे और उसके बाद हुई परीक्षा में 1000 से भी अधिक महिलाओं उम्मीदवारों ने इसे पास किया है। इन महिला उम्मीदवारों को अब आगे की चयन प्रक्रिया के तहत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) के मानकों तथा मेडिकल फिटनेस की कसौटी पर खरा उतरना होगा। परीक्षा पास करने वाली 1002 महिला उम्मीदवारों में से केवल 19 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। समूची चयन प्रक्रिया के आधार पर अगले कोर्स के लिए 400 उम्मीदवारों को चुना जाना है जिनमें 19 स्थान महिलाओं के लिए रखे गए हैं।

पति ने पत्नी और 2 बच्चों को खिलाया जहरीला पदार्थ, तीनों की हुई मौत

पटना (आरएनएस)। बिहार के नालंदा जिले के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी और दो मासूम के खाने में जहरीला पदार्थ खिलाकर मार देने का आरोप लगा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या के पीछे दहेज का मामला बताया जा रहा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बड़इचक गांव निवासी गुड्डू पासवान पर अपनी ही पत्नी और दो बच्चों की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने बताया कि आरोप है कि दहेज नहीं देने पर पति ने पत्नी और अपने दो बच्चों को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पति द्वारा दहेज की खातिर महिला के साथ मारपीट किया करता था। मृतकों की पहचान ज्ञानती देवी और उसके पुत्र साहिल कुमार (3) और पुत्री स्नेहा कुमारी (1) के रूप में की गई है।

84 दंगा पीड़ितों के 73 परिवारों को आने वाले दिनों में नौकरी भी मिलेगी : सिरसा

नई दिल्ली (आरएनएस)। भाजपा के सिख नेता मनजिन्दर सिंह सिरसा ने कहा है कि 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ित 114 परिवारों को जल्दी ही उनकी बकाया रहती एक्स ग्रेशिया मुआवजा राशि मिल जाएगी और 73 परिवारों को जल्दी ही उनके सदस्यों के लिए नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे। इस मामले में डिविजनल कमिशनर दिल्ली संजीव खिरवार के साथ मीटिंग करने उपरांत जारी किए एक बयान में सरदार सिरसा ने बताया कि उन्होंने कुछ पीड़ित परिवारों का एक्स ग्रेशिया मुआवजा बकाया होने का मामला उठाया था। इसके जवाब में डिविजनल कमीशन ने उनको बताया है कि एक्स ग्रेशिया की 114 फाइलें क्लीयर की जा रही हैं और इन परिवारों को बिना और देरी के मुआवजा मिला जाएगा।

स्किन-टू-स्किन टच बिना रेप नहीं का फैसला देने वाली जज का हुआ डिमोशन

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पुष्पा वी गनेडीवाला के नाम की सिफारिश बॉम्बे हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नहीं करने का फैसला किया है। गनेडीवाला वहीं जज हैं, जिनके एक फैसले ने काफी विवाद खड़ा किया था। उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि अगर पीड़िता और आरोपी के बीच स्कीन-टू-स्कीन टच नहीं हुआ है तो इसे यौन अपराध नहीं माना जाएगा।

जस्टिस गनेडीवाला वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट की अतिरिक्त जज हैं। कॉलेजियम के इस फैसले का मतलब है कि उन्हें वापस जिला न्यायपालिका में भेज दिया जाएगा। हाईकोर्ट में नियुक्तियों का निर्णय लेने वाले कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ शामिल हैं। हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224(1) के तहत सीधे बार या राज्य न्यायपालिका से दो साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाती है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।

दिल्ली, यूपी समेत कई इलाकों में बढ़ेगा शीतलहर का कहर, शिमला में माइनस में पहुंचा तापमान

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब समेत उत्तर भारत में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। यही नहीं आने वाले दिनों में यह और तेज हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम और ठंडा हो गया है। शुक्रवार को उत्तराखंड में भी बर्फ गिरने की आशंका है। यही नहीं अगले कुछ दिनों तक शीत लहर का कहर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर क्रिसमस और नए साल के मौके पर सर्दी और तेज हो सकती है। इसकी वजह यह है कि 22 और 23 दिसंबर को हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगले 15 दिनों तक भीषण सर्दी बनी रह सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 दिसंबर को भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हालांकि इससे पर्यटकों को खुशी मिल सकती है, जो पहाड़ी इलाकों में नए साल के मौके पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए जाना चाहते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सुबह न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के करीब ही रहा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यहां बादल के साथ बारिश की संभावना भी बताई है। इसके बाद यहां ठंड और बढ़ने के आसार हैं।

शिमला में माइनस में गया पारा, झीलों का पानी बना बर्फ

इस बीच हिल्स क्वीन शिमला में पारा माइनस में चला गया है। 15 दिसंबर की रात को शिमला का तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली एनबीसीसी के ऊपर एक करोड़ का जुर्माना लगाया

» सरकार के रोक के बावजूद एनबीसीसी ने रात के अंधेरे में काम किया : गोपाल राय

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने रोक के बावजूद निर्माण कार्य करने पर एनबीसीसी के ऊपर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नेताजी नगर में एनबीसीसी की साइट पर रात के अंधेरे में काम किया जा रहा था। साइट को भी सील करने के निर्देश दिए गए हैं। डीपीसीसी की टीम ने एनबीसीसी की साइट पर 3 दिसंबर को भी छापे मारे थे। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 5 लाख का जुर्माना लगाया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्यों पर बैन है। किसी तरह का उल्लंघन पाया गया तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार ने 11 नाइट पेट्रोलिंग दस्ता का भी गठन किया है जो रात्रि में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्यों पर नजर रखेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्यों पर बैन लगा हुआ है। इसके अलावा बाहर से आने वाले ट्रकों पर भी रोक लगी हुई है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया गया है कि नियम के उलंघन करने वाले पर सख्त एक्शन लें। उन्होंने कहा कि नेताजी नगर में एनबीसीसी की साइट पर रात के अंधेरे में काम किया जा रहा था। एनबीसीसी की साइट पर 3 दिसंबर को भी डीपीसीसी की टीम ने छापे मारे थे। जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन देखा गया था। इसके बाद नोटिस देकर 5 लाख का जुर्माना लगाया था।

गोपाल राय ने कहा कि अब दोबारा कंपनी को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। इसके बाद डीपीसीसी, ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और एमबीसीसी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। एनबीसीसी के बार-बार के उल्लंघन को देखते हुए कंपनी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेताजी नगर की साइट को तत्काल प्रभाव से सील करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर अभी कंट्रक्शन-डिमोलिशन पर बैन है। इसको लेकर कई एजेंसियों के हमारे पास प्रस्ताव आए हैं। जिसे सेंट्रल कमीशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के पास भेजा गया है कि वो उस पर निर्णय लें। दिल्ली के अंदर में सभी एजेंसियों को आगाह करना चाहता हूं जब तक इस पर निर्णय नहीं होता है तब तक अगर किसी तरह का कोई उल्लंघन पाया गया तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

पीएम मोदी के नाम एक और उपलब्धि, भूटान ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुनिया के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय नेता हैं। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेल गि खोरलो से सम्मानित किया है। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। भूटान सरकार ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल गि खोरलो से सम्मानित किया गया है। भूटान के प्रधान मंत्री के एक ट्वीट में कहा, महामहिम ने सर्वोच्च नागरिक अलंकरण के लिए महामहिम मोदी जी के नरेंद्र मोदी नाम, नगदग पेल जी खोरलो का उच्चारण सुनकर बहुत खुशी हुई।

जानकारी देते हुए भूटान पीएम कार्यालय ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना किसी शर्त के दोस्ती, भूटान के लिए उनके समर्थन और विशेष तौर पर कोरोना महामारी के दौरान की गई मदद के लिए भूटान उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने का फैसला किया है। आगे लिखा गया है कि भूटान का हर नागरिक उन्हें इसके लिए बधाई देता है। इस उपलब्धि पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को बधाई भी दी है।

दिल्ली में फिर ओमिक्रॉन का विस्फोट, मिले 10 नए केस, देश भर में कुल मामले बढ़कर 97 हुए

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट का विस्फोट हुआ है। शुक्रवार को राजधानी में ओमिक्रॉन वैरिएंट के 10 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 20 हो गए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के कुल केस 100 के करीब (97) पहुंच गए हैं। इससे पहले देश भर में ओमिक्रॉन वैरिएंट के 14 केस पाए गए थे। इनमें से 5 मामले कर्नाटक मिले थे, जबकि 4-4 केस दिल्ली और तेलंगाना में पाए गए थे। 1 नया केस गुजरात में पाया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से 10 लोग फिलहाल डिस्चार्ज हो गए हैं। इस तरह देखें तो राजधानी में ओमिक्रॉन वैरिएंट के ऐक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 10 ही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नए केसों के मिलने की जानकारी दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले दिनों कहा था कि यदि ओमिक्रॉन वैरिएंट के केस आते हैं तो उनसे निपटने के लिए तैयारी पूरी है।

इस बीच देश में शुक्रवार को बीते एक दिनों में कोरोना के 7,447 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 830 सक्रिय मामले घटे हैं। इससे एक्टिव केसों की संख्या घट कर 86,415 हो रह गई है। इस बीच कल देश में 70 लाख 46 हजार 805 कोविड टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही कुल टीकाकरण संख्या एक अरब 35 करोड़ 99 लाख 96 हजार 267 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7447 नए मामले सामने आए और इस दौरान 7,886 मरीज स्वस्थ होने के साथ इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या बढ़कर तीन करोड़ 41 लाख 62 हजार 765 हो गयी है।

रिकवरी रेट में तेजी से इजाफा, केरल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस

देश में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर 98.38 फीसदी, सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.37 फीसदी पर बरकरार है। वर्तमान में देश में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले केरल में हैं। यहां पिछले 24 घंटों में 1061 सक्रिय मामले घटने से इनकी कुल संख्या घटकर 34,836 रह गई है। राज्य में 4,145 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोनामुक्त होने वालों की तादाद बढ़कर 51,29,044 हो गई है।

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़े हैं कोरोना के एक्टिव केस

इसी अवधि में 320 मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 43,946 हो गयी है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 226 सक्रिय मामले बढ़ने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 10372 हो गयी है, जबकि 19 और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,41,317 हो गया है। वहीं 632 और मरीजों के कोरोना मुक्त होने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 64,95,249 हो गई है।